POSTAL REG. NO. JAIPURCITY/410/2015-17 (RNI. REG. NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2016/अंक 12

मासिक प्रेषण दि. 8 दिसम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 दिसम्बर, 2016 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम!

गांव-ढाणी से उठकर खबर आ रही है 'बेईमानी से कमाया हजार पांच सौ का नोट ज्यांकन छै, बै भागता फिर रह्या छै'।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कालेधन के खिलाफ उठाए गए इस कदम को करीब 80 फीसदी से भी ज्यादा लोगों ने सराहा है। उनका मानना यह भी है कि इस फैसले से आम व्यक्ति को कुछ तकलीफें जरूर हुई हैं, लेकिन उम्मीद जताई है कि कुछ समय बाद इसके नतीजे अच्छे आएंगे।

गांवों में पुराने नोट बदलाने और जमा कराने वालों की लगी लम्बी लाइन में खड़े लोगों से जब इस बाबत बात की तो उनका कहना था कि लोगों को परेशानी नहीं हो, इसके लिए भी जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए। ताकि लोगों को शादी विवाह, खेती-बाडी, बीमारी के इलाज एवं घरेलू जरूरतों को पूरा करने के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़े।

गांव के एक नवयुवक ने जागरूकता का परिचय देते हुए कहा 'इस फैसले से पहले मोदीजी ने कालेधन वालों को पैसा जमा कराने और चैन की नींद सोने का मौका दिया था, लेकिन इसकी परवाह नहीं की गई। गांवों में काला धन नहीं होता, वह तो शहरों में बसे रईसों के पास हैं। वे अब काले धन को सफेद करने की जुगत में लगे हैं।'

बहरहाल, मोदी ने कहा है कि कालेधन के खिलाफ दूसरी कोई स्कीम नहीं लाऊंगा इसकी गारंटी नहीं है। सरकार की हर स्थिति पर पूरी नजर है। बेशक, यह फैसला ईमानदार, गरीब व मेहनतकश लोगों के लिए के हित में होगा और देश मजबूत होकर उभरेगा...!!

एटीएम का भी होता है बीमा, बैंक बताते नहीं

क्या आपको पता है कि हादसे में किसी की मौत हो जाए और मृतक डेबिट या क्रेडिट कार्ड धारक हो तो उसे 1 से 10 लाख रुपए तक दुर्घटना बीमा क्लेम मिलना चाहिए। नहीं पता तो आज जान लीजिए क्योंकि सरकारी हो या निजी, बैंक तो कभी बताते ही नहीं कि ऐसा कोई प्रावधान भी है।

यह है प्रक्रिया...

कार्ड से लेन-देन का बैंक से रिकॉर्ड लेकर बैंक में एक्सीडेंटल क्लेम फॉर्म भरा जाए। हादसे में मौत होने पर एफआईआर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मृत्यु प्रमाण-पत्र व पंचनामा बैंक अधिकारी को दिया जाए। रिजर्व बैंक के अनुसार कार्ड धारक का बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए। हादसे में विकलांगता पर भी क्लेम मिलता है।

हादसे के बाद मदद देने-दिलाने वाले पुलिसकर्मियों और जिम्मेदारों को भी इस बारे में प्रायः पता नहीं होता। यही कारण है कि राजधानी जयपुर में ही बीते 8 महीनों में सड़क हादसों में मृत 262 लोगों में से किसी के भी परिवार वालों को ऐसा कोई बीमा क्लेम नहीं मिला। जबकि इनमें से 95 फीसदी लोग डेबिट या क्रेडिट कार्ड धारक थे।

बैंक ग्राहकों को डेबिट या क्रेडिट कार्ड के साथ मोबाइल-नेट बैंकिंग सहित अन्य जानकारियां तो देते हैं लेकिन बीमा पॉलिसी के बारे में नहीं बताते। यही कारण है कि हादसे के बाद कई बार हंगामा होने, मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक मदद मिलने के बाद भी कार्ड की बीमा पॉलिसी के तहत मिलने वाली राशि से आश्रित परिवार वंचित रह जाता है।

आवासीय योजना निरस्त की अब देना होगा ब्याज सहित हर्जाना

मानसरोवर निवासी अशोक चौधरी, पत्नी मंजू चौधरी एवं कूकरखेड़ा निवासी सास शारदा देवी ने उपभोक्ता मंच जयपुर (तृतीय) में ओमेक्स लिमिटेड कंपनी (नई दिल्ली) के खिलाफ परिवाद दर्ज कराया। उन्होंने परिवाद में मंच को बताया कि कंपनी के लुभावने विज्ञापन से प्रभावित होकर 2008 में प्लॉट बुक कराए थे। कंपनी ने तीनों को बुकिंग के समय जमा कराई गई अग्रिम राशि की रसीदें भी जारी की थी। लेकिन कंपनी ने 27 सितंबर 2010 को आवासीय योजना निरस्त करते हुए अग्रिम राशि के चैक लौटा दिए। इससे न केवल उनका मकान मिलने का सपना चकनाचूर हो गया बल्कि कंपनी ने उनके पैसे दो साल तक अपने पास जमा रखे और उसका ब्याज भी नहीं दिया।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने मकान का सपना दिखाकर धोखाधड़ी करने, बुकिंग निरस्त करने और जमा राशि पर ब्याज अदा नहीं करने को गंभीर सेवा दोष माना। उपभोक्ता मंच ने ओमेक्स लि. कंपनी (नई दिल्ली) पर एक लाख 50 हजार रुपए का हर्जाना लगाया है। साथ ही तीन उपभोक्ताओं के दो साल तक जमा 9 लाख 20 हजार रुपए मय ब्याज के अदा करने के आदेश दिए हैं।

बेहतरी के लिए किसान अपनाएं जैविक खेती

'खेती में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के अत्यधिक उपयोग से खाने-पीने की चीजों में जहर घुल रहा है। इससे लोगों के स्वास्थ्य पर काफी बुरा प्रभाव पड़ रहा है। इससे जमीन की उपजाऊ शक्ति कम हो रही है और पर्यावरण पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। किसानों को अपनी व आने वाली पीढ़ियों की बेहतरी के लिए जैविक खेती को अपनाना जरूरी हो गया है।'

यह तथ्य 'कट्स' द्वारा जयपुर स्थित राजस्थान गौ सेवा संघ, दुर्गापुरा में आयोजित जिला स्तरीय कृषक आमुखीकरण कार्यशाला में उभर कर सामने आए। कार्यशाला के तकनीकी सत्रों में जैविक खेती की जरूरत और इसके महत्व पर प्रकाश डालते हुए वी.एस. यादव, प्रोफेसर, होर्टिकल्चर राजस्थान कृषि शोध संस्था ने जैविक खेती के तरीकों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कृषि विशेषज्ञ अमित शर्मा ने जैविक खेती की व्यावसायिक संभावनाओं के बारे में जानकारी दी। 'कट्स' परियोजना अधिकारी राजदीप पारीक ने जैविक खेती के विभिन्न तरीकों से सहभागियों को अवगत कराया। विषय विशेषज्ञों ने बताया जैविक खेती को सुव्यवस्थित तरीके से करने पर मिट्टी की शक्ति और पोषक तत्व बढ़ेगा। जिससे उत्पादन में भी वृद्धि होगी।

प्रारंभ में 'कट्स' के डिप्टी हैड, दीपक सक्सेना ने परियोजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि साल के दौरान प्रशिक्षण, पैरवी, किसान मेला, शैक्षणिक भ्रमण आदि गतिविधियां आयोजित की जा रही है।

खराब होने लगी सोलर लाइटें

ग्राम पंचायतों की सोलर लाइटें मरम्मत के अभाव में खटारा होती जा रही है। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देशों के बावजूद अभी भी मरम्मत का काम फाइलों में ही घूम रहा है। जन-प्रतिनिधियों और जिला परिषदों के बीच कई बार लिखित शिकायतों के बावजूद कार्रवाई में सुस्ती का आलम है।

सोलर लाइटें लगाने में ग्राम पंचायतों में भारी भ्रष्टाचार के बाद पंचायतीराज विभाग ने नई सोलर लाइटें लगाने के प्रस्ताव को तो ठंडे बस्ते में ही डाल दिया। अब लाइटें बदहाल होने पर भी नहीं बदली जा रही। समय पर मरम्मत नहीं होने से तकरीबन 25 जिलों के गांवों से रोशनी गायब है।

अल्पसंख्यक महिलाओं को ब्याज में छूट

अल्पसंख्यक महिलाओं को लघु उद्योग व खुद का रोजगार शुरू करने के लिए 20 लाख रुपए तक के ऋण पर ब्याज में पूरी तरह छूट मिलेगी। महिला समृद्धि योजना के तहत किसी भी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से वह स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए 20 से 50 लाख रुपए तक का ऋण ले सकेंगी।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि महिला समय पर ऋण चुकाएगी तभी अंतिम किश्त पर उसे ब्याज की छूट मिलेगी। योजना के तहत स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से कौशल विकास का प्रशिक्षण देने की योजना भी शुरू की गई है।

प्रदेश के मजदूरों को मिलेगी पेंशन

प्रदेश सरकार जल्द ही मजदूरों को पेंशन का बड़ा तोहफा देने जा रही है। इससे साठ की उम्र पार कर चुके मजदूरों को दो जून की रोटी के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। योजना के तहत रिटायर्ड मजदूरों को प्रति माह एक हजार रुपए पेंशन दी जाएगी।

भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिक कल्याण मंडल के माध्यम से यह स्कीम लाई जा रही है। पेंशन योजना श्रम विभाग के अधीन ऐसे रजिस्टर्ड मजदूरों को मिलेगी जो सरकार की तय उम्र, साठ साल को पार कर चुके होंगे। नरेगा में शामिल मजदूरों को भी इस स्कीम से जोड़ा जाएगा।

जल संरक्षण में जिला परिषदें सुस्त

पंचायतीराज विभाग ने भूजल विभाग के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश की 296 पंचायत समितियों में से 204 पंचायत समितियों को डार्कजोन में माना है। पानी के संकट को देखते हुए जल संरक्षण के प्रति सरकार गंभीर है, लेकिन ज्यादातर जिला परिषदें इस कवायद को अंजाम तक नहीं पहुंचा सकीं।

विभागीय समीक्षा में सामने आया है कि प्रदेश की करीब 70 फीसदी पंचायत समितियों में वॉटर हार्वेस्टिंग सिस्टम सिर्फ फाइलों में दबे पड़े हैं। मानसून गुजर जाने के बाद भी जिला परिषदें जल संरक्षण के सरकारी उद्देश्य को पूरा करने में असफल रही हैं। विभाग ने इसे गंभीरता से लिया है और जिला परिषदों को फिर से अपनी जिम्मेदारी याद दिलाई है।

उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन

प्रदेश में उपभोक्ताओं के कल्याण को प्रोत्साहन, संरक्षण एवं उपभोक्ता आंदोलन को मजबूत करने के लिए राजस्थान उपभोक्ता कल्याण कोष का गठन किया गया है। इस कोष से मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों को आर्थिक सहायता अनुदान देने का भी प्रावधान है।

इस कोष के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने व कल्याण कोष में जमा धन के उचित उपयोग की सिफारिश करने के लिए विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में स्थाई समिति का गठन किया गया है। इसमें उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों का रोस्टर के अनुसार दो साल के लिए सदस्य बनाने का प्रावधान है।

चूल्हें के धुएं से मुक्त होगा प्रदेश

राजस्थान अगले 3 सालों में चूल्हे के धुएं से मुक्त हो जाएगा। केन्द्र सरकार की उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन जारी करने की तेज गति से ऐसा लगने लगा है। इस योजना में उतने गैस कनेक्शन तो 6 महीने में ही दे दिए गए जितने अब तक सालभर में दिए जाते रहे हैं।

प्रदेश में रसोई गैस कनेक्शन का आंकड़ा एक करोड़ परिवारों को पार कर गया है। योजना के तहत प्रदेश में एक साल में 1.5 करोड़ गरीब परिवारों को गैस कनेक्शन देने हैं। अब तक 50 फीसदी से भी अधिक लक्ष्य पूरा किया जा चुका है।

कालेधन पर रोक

मैं प्रधानमंत्री के 500 व 1000 रुपए के नोटों पर रोक के निर्णय का स्वागत करता हूं। इस निर्णय से कालेधन, भ्रष्टाचार और आतंकवाद पर अंकुश लगेगा। आमजन इस फैसले से राहत महसूस कर रहा है। इससे लोगों को नोट बदलवानें में काफी परेशानी भी उठानी पड़ रही है। लेकिन जिनके पास कालाधन है वे चैन से सो नहीं पा रहे। वे इस धन को सफेद करने की जुगत में लगे हैं।

मोदी सरकार की सभी स्थितियों पर गहरी नजर है। जरूरत के मुताबिक बैंकिंग व्यवस्था में भी सुधार किया जा रहा है ताकि लोग परेशान नहीं हो।

-चन्द्र प्रकाश बागड़ा, प्रतापगढ़

गरीबी मिटाने की चुनौती स्वीकार

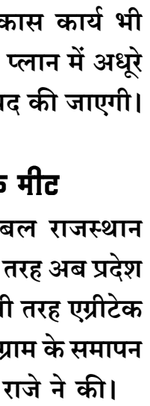

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि देश से गरीबी मिटाना एक चुनौती है जिसे उन्होंने स्वीकार किया है और उनकी सरकार इस दिशा में गंभीरता से काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि गरीबी मिटाना कठिन काम है। इसे विकास कार्यों के जरिए ही मिटाया जा सकता है। गरीबी से निजात पाने का एक मात्र उपाय सर्वांगीण विकास है। गरीब को सामर्थ्यवान बनाकर और लोगों को रोजगार उपलब्ध कराकर गरीबी मिटाई जा सकती है। भारत में हुनर की कमी नहीं है। लेकिन इसके लिए लोगों को प्रशिक्षित करना बहुत जरूरी है।

आदर्श गांव की कछुआ चाल

आदर्श ग्राम पंचायत योजना के चयनित गांवों में विकास कार्यों की कछुआ चाल से ग्रामीण विकास विभाग की चिंता बढ़ने लगी है। अब विभाग पिछड़े जिलों की बेबसी जानकर शेष वित्तीय वर्ष में काम पूरा करने का प्लान तैयार करेगा।

जिला परिषदों से स्वीकृत कार्यों का ब्योरा भी मांगा गया है। पिछले वित्तीय वर्ष में चयनित आदर्श ग्राम पंचायतों के विकास कार्य भी कई जिलों में अधूरे पड़े हुए हैं। प्लान में अधूरे कार्यों को पूरा करने की कवायद की जाएगी।

हर संभाग में होगी एग्रीटेक मीट

जयपुर में सम्पन्न हुई ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट 2016 (ग्राम) की तरह अब प्रदेश के सभी संभाग स्तर पर भी इसी तरह एग्रीटेक मीट (ग्राम) होगी। यह घोषणा ग्राम के समापन समारोह में मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की।

उन्होंने कहा कि भूमिहीन काश्तकारों को कृषि योग्य भूमि का नियमानुसार आवंटन एवं नियमन किया जाएगा। औषधीय पौधों के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे, जिन्हें स्किल डवलपमेंट से जोड़ा जाएगा। केन्द्र सरकार के सहयोग से 'स्किल विले' विकसित किए जाएंगे।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

भारत सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता मामले मंत्रालय के सौजन्य से 'कट्स' इन्टरनेशनल द्वारा ग्राहक सुविधा केन्द्र की स्थापना की गई है।

ग्राहक सुविधा केन्द्र

आप उपभोक्ता सम्बन्धित किसी भी तरह की जानकारी अथवा शिकायत के लिए निम्न पते पर सम्पर्क कर सकते हैं।

ग्राहक सुविधा केन्द्र
कंज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी (कट्स)
डी-218 ए, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016
ई-मेल: gsk@cuts.org फोन +091.141.4015395

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर